विचार बिन्दु

कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। –कहावत

जल संरक्षण हेतु सरकारी योजनाएं : राजस्थान की दिशा और देश के लिए प्रेरणा

राजस्थान सदियों से जल संकट से जूझता रहा है। विशाल थार मरुस्थल, औसतन मात्र 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा, और भूजल का अनियंत्रित दोहन - ये सभी कारक मिलकर इस प्रदेश के लिए पानी को सबसे बडी चुनौती बना चुके हैं। यहां पानी केवल जीवन की आवश्यकता नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। राजस्थान की संस्कृति और परंपरा ने सदैव पानी को विशेष महत्व दिया है। इसी कारण यहाँ की वास्तुकला में बावड़ी, टांका, नाड़ी और जोहड़ जैसी जल संरचनाएँ दिखाई देती हैं। इन पारंपरिक स्त्रोतों ने सदियों तक समाज की प्यास बुझाई, लेकिन आधुनिकता और लापरवाही ने इन्हें उपेक्षित कर दिया। आज जब जल संकट विकराल रूप ले चुका है, तब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अनेक योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास कर रही हैं।

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में सबसे बड़े स्तर पर जल प्रबंधन के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई। इसने जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे सूखे क्षेत्रों में हरियाली और खेती को संभव बनाया। लेकिन बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण के दबाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल नहरों या बड़े बांधों से समस्या का समाधान नहीं होगा। जल संकट से निपटने के लिए छोटे स्तर पर सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण को बढ़ावा देना आवश्यक है। यही सोच राजस्थान की अनेक योजनाओं की आधारशिला बनी।

राजस्थान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था - हर गाँव को जल स्वावलंबी बनाना। इसके अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार, जोहड़ और बावड़ियों का पुनर्निर्माण, चेकडैम और एनिकट का निर्माण, खेत-तालाब और टांका जैसी संरचनाएँ बनाई गईं। योजना की विशेषता यह रही कि इसमें ग्राम पंचायतों और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। हजारों गाँवों में इस अभियान से भूजल स्तर में सुधार हुआ और किसानों की सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने में मनरेगा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तालाब, खेत-तालाब, टांका, नाड़ी, चेकडैम और जल निकासी नालों का विकास किया गया। इसने न केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि जल संचयन की स्थायी संरचनाएँ भी बनाईं। राजस्थान के अनेक गाँवों में आज मनरेगा के कार्यों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है।

भूजल संकट से जूझ रहे राजस्थान में अटल भूजल योजना को भी लागू किया गया। राज्य के सात जिलों में शुरू इस योजना का लक्ष्य है-जल उपयोग का संतुलन और भूजल का पुनर्भरण। पंचायतों को इस योजना में भागीदार बनाकर उन्हें जल बजट तैयार करने और हर बूंद के महत्व को समझाने की जिम्मेदारी दी गई। इस पहल ने ग्रामीण समाज को जल प्रबंधन की दिशा में सक्रिय किया।

पेयजल की समस्या राजस्थान में सबसे गंभीर रही है। विशेषकर ग्रामीण महिलाएँ मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर थीं। इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हजारों गाँवों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इससे महिलाओं को राहत मिली है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी कम हुई हैं। लेकिन इस योजना का उद्देश्य केवल नल कनेक्शन देना नहीं है, बल्कि जल स्त्रोतों का संरक्षण और पुनर्भरण भी इसमें शामिल है।

राजस्थान की परंपरा ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का मूल है। सरकार की योजनाएँ इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। यदि यह प्रयास लगातार जारी रहे और समाज इसमें सक्रिय रूप से भाग ले, तो राजस्थान न केवल अपने जल संकट से उबर सकेगा, बल्कि पूरे देश के लिए जल संरक्षण की प्रेरणा बन सकता है।

कृषि क्षेत्र, जो राज्य के कुल जल उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। इसी सोच के साथ लागू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने राजस्थान के किसानों को नई राह दिखाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों से कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हुआ। सीकर, झुंझुनूं, चूरू और जोधपुर जैसे जिलों में किसान अब इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर पानी की बचत कर रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी जल संकट तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन बड़ी समस्या है। इस दिशा में अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया गया है। अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं ताकि पानी का पुन: उपयोग किया जा सके। इससे न केवल जल संरक्षण हो रहा है बल्कि शहरी स्वच्छता में भी सुधार आ रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कैच द रेन अभियान का प्रभाव भी राजस्थान में देखा जा सकता है। ''जहाँ गिरे, जब गिरे, पानी को सहेजें'' के नारे के साथ लोगों को अपने घरों और खेतों में वर्षा जल संचयन की तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विद्यालयों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

राजस्थान में जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रश्न है। अलवर जिले के जोहड़ों का पुनर्जीवन, पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह के प्रयासों से देश और दुनिया के लिए मिसाल बना। उनके प्रयासों से पुनर्जीवित जल स्त्रोतों ने न केवल भूजल स्तर बढ़ाया, बल्कि नदियों को भी पुनर्जीवित किया। इसी तरह के प्रयास यदि हर जिले में हों तो सरकारी योजनाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। इन सभी योजनाओं में पहलें से यह स्पष्ट है कि राजस्थान ने जल संरक्षण की दिशा में एक नई सोच और नई नीति अपनाई है। लेकिन चुनौतियाँ अभी भी शेष हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को और भी अस्थिर बना दिया है। ऐसे में योजनाओं की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। जल की एक-एक बूंद बचाना आज जीवन रक्षा का मंत्र है।

राजस्थान की परंपरा ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का मूल है। सरकार की योजनाएँ इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। यदि यह प्रयास लगातार जारी रहे और समाज इसमें सक्रिय रूप से भाग ले, तो राजस्थान न केवल अपने जल संकट से उबर सकेगा, बल्कि पूरे देश के लिए जल संरक्षण की प्रेरणा बन सकता है।

–अतिथि सम्पादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

नेपाल संकट : डीप स्टेट और एशिया की राजनीति

मुरारी गुप्ता

सिर्फ़ दो दिनों में नेपाल की सियासी ज़मीन हिल गई। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन तक विद्रोही युवाओं के निशाने पर आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ मारपीट हुई और सत्ता का तख़्ता पलट लगभग तय हो गया। यह सब अचानक नहीं था। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वर्षों से जिस पैटर्न पर घटनाएँ घट रही हैं-श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल-वह यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं डीप स्टेट यानी अमेरिकी रणनीतिक तंत्र की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं।

डीप स्टेट क्या है?

अमेरिका की राजनीति में अक्सर यह शब्द सामने आता है। इसका आशय उन शक्तिशाली संस्थानों से है जो चुनी हुई सरकारों से परे काम करते हैं-जैसे खुफिया एजेंसियाँ, थिंक टैंक, रक्षा ठेकेदार, मीडिया लॉबी और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट। इनकी प्राथमिक चिंता वैश्विक प्रभुत्व और अपने हितों की रक्षा होती है। जब भी कोई देश अमेरिकी हितों से अलग रास्ता चुनता है, वहाँ अस्थिरता पैदा करना इस तंत्र का पुराना हथियार है। इराक़, लीबिया, सीरिया इसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन अब यह रणनीति एशिया की उभरती राजनीति में भी देखने को मिल रही है, जहाँ चीन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है।

नेपाल क्यों निशाने पर?

नेपाल का भौगोलिक महत्व किसी से छुपा नहीं। भारत और चीन के बीच बसा यह हिमालयी राष्ट्र दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीति से जुड़ा है। बीते कुछ वर्षों में काठमांडू ने चीन के साथ आर्थिक और राजनीतिक नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में नेपाल की भागीदारी और निवेश पर अमेरिका की नज़र लंबे समय से टिकी हुई है।

अमेरिका नहीं चाहता कि चीन हिमालय से होकर दक्षिण एशिया में और गहरी पैठ बनाए। ऐसे में नेपाल में अचानक भड़का युवा विद्रोह, लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाना और सरकार को गिराने की ज़िद एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय पटकथा का हिस्सा प्रतीत होती है।

जेनरेशन ज़ी या 'मैन्युफैक्चर्ड' गुस्सा?

नेपाल में जिन युवाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें जेनरेशन ज़ी का नाम देकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया गया। कहा गया कि वे भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ़ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि महज़ दो दिन में इतना बड़ा तंत्र कैसे खड़ा हो गया? पुलिस और सेना की अचानक लाचारी, संगठित भीड़ की तैयारियाँ और लोकतांत्रिक ढाँचों को सीधा निशाना बनाना यह दर्शाता है कि आंदोलन स्वत: स्फूर्त कम और योजनाबद्ध ज़्यादा था। यह वही फार्मूला है जो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ़ दिखा और श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भी अपनाया गया।

भारत के लिए चेतावनी

नेपाल की अस्थिरता भारत के लिए सीधा खतरा है। सुरक्षा दृष्टि से खुली सीमा के कारण नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता भारत के सीमावर्ती राज्यों तक असर डाल सकती है। चरमपंथी और विदेशी ताक़तें इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं। भूराजनीतिक दृष्टि से भी अगर नेपाल में चीन समर्थक या अमेरिका समर्थक ताक़तें बारी-बारी से खेल रचेंगी तो भारत बफ़र ज़ोन की सुरक्षा खो देगा। नेपाल को लेकर भारत की पारंपरिक 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति चुनौती में आ सकती है। सोशल मीडिया, नैरेटिव वॉरफेयर और भ्रामक प्रचार का असर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ सकता है।

कमजोर नेतृत्व, मजबूत नैरेटिव

नेपाल की मौजूदा राजनीति यह भी दर्शाती है कि कमजोर नेतृत्व किसी भी देश को बाहरी हस्तक्षेप के लिए खुला छोड़ देता है। जब नेतृत्व अस्थिर होता है, तब नैरेटिव की राजनीति ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। डीप स्टेट इसी कमजोरी को भुनाता है। भारत के लिए सबक साफ़ है-सिर्फ़ मजबूत नेतृत्व ही नहीं, बल्कि सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाएँ और सतर्क जनता ही किसी भी बाहरी नैरेटिव को विफल कर सकती हैं। नेपाल की आग केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। यह दक्षिण एशिया की भूराजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जिसमें अमेरिका की डीप स्टेट, चीन की महत्वाकांक्षाएँ और भारत की सुरक्षा हित तीनों टकरा रहे हैं।

आज सवाल केवल नेपाल की स्थिरता का नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का है। अगर बाहरी ताक़तें बार-बार लोकतंत्र और युवाओं की ऊर्जा को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगी तो अगली अस्थिरता की लपटें किसी और पड़ोसी देश तक पहुँच सकती हैं। भारत को इस पर पैनी नज़र रखनी होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया में उठता हर धुआँ उसकी सीमाओं को ही सबसे पहले घेरता है।

–मुरारी गुप्ता
(लेखक उपन्यासकार हैं)।

राजनीतिक प्रदूषण: पर्यावरणीय संकट का एक अदृश्य कारण

अशोक कुमार

आज जब हम पर्यावरणीय संकट की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में प्रदूषण फैलाने वाले कारक जैसे कि उद्योग, वाहनों का धुआँ, प्लास्टिक कचरा, पेड़-पौधों की कटाई आदि आते हैं। लेकिन इन समस्याओं के पीछे एक और बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अदृश्य कारक होता है, जिसे हम 'राजनीतिक प्रदूषण' कह सकते हैं। यह वह प्रदूषण है जो सीधे हवा, पानी या मिट्टी को तो प्रदूषित नहीं करता, लेकिन नीतियों, फैसलों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के माध्यम से प्रदूषण की समस्या को और जटिल बना देता है।

राजनीतिक प्रदूषण एक ऐसा सामाजिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य है, जो यह बताता है कि किस प्रकार राजनीतिक निर्णय, लापरवाही, भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति के चलते पर्यावरणीय संकटों को रोकने की कोशिशें कमजोर पड़ जाती हैं। यह सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को बाधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण की समस्या के समाधान में आने वाली राजनीतिक बाधाओं को उजागर करना है, जैसे कि कानूनों का अभाव, कार्यान्वयन में लचरता, जिम्मेदारी से बचाव और केवल चुनावी लाभ के लिए पर्यावरण का उपयोग। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाने की प्रक्रिया में अक्सर सरकारें धीमी होती हैं। कई बार सालों तक जरूरी कानून या नीतियाँ केवल मसौदे के स्तर पर अटकी रह जाती हैं। प्रदूषण जैसे आपातकालीन मुद्दों पर भी नीतिगत निर्णयों में देरी होती है। उद्योगपतियों और राजनीतिक वर्ग के बीच गठजोड़ राजनीतिक प्रदूषण का एक अहम हिस्सा है। कई बार बड़ी कंपनियाँ प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे राजनीतिक चंदा, लॉबिंग और सत्ता-संबंधी हित छिपे होते हैं।

प्रत्येक चुनाव के समय राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के बड़े-बड़े वादे करते हैं - जैसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ नदियाँ, हरे-भरे शहर आदि। लेकिन सत्ता में आने के बाद अक्सर ये वादे अधूरे रह जाते हैं।

जब प्रदूषण का स्तर चरम पर होता है - उदाहरण के लिए दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण - तो राजनीतिक दल एक-दूसरे पर दोष मढ़ने में लग जाते हैं। कोई पराली जलाने को दोष देता है, तो कोई नगर निगम की लापरवाही को। लेकिन वास्तविक समाधान के लिए सामूहिक पहल नहीं होती।

राजनीतिक दल कई बार प्रदूषण से निपटने के लिए केवल प्रतीकात्मक और अस्थायी कदम उठाते हैं, जैसे कि 'सम-विषम योजना', 'एंटी-स्मॉग गन' या 'ग्रीन वीक'। ये कदम लंबे समय तक चलने वाले प्रभावशाली समाधान नहीं होते, बल्कि केवल जनता को यह दिखाने के लिए होते हैं कि सरकार कुछ कर रही है।

राजनीतिक निर्णयों के चलते पर्यावरणीय संसाधनों - जैसे पानी, जंगल, जमीन - का असमान वितरण होता है। बड़ी विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी इलाकों से जंगलों को उजाड़ा जाता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और गरीब समुदायों का जीवन प्रभावित होता है।

कई बार सरकारें यह तर्क देती हैं कि 'विकास' के लिए पर्यावरणीय बलिदान जरूरी है। लेकिन इस विकास का लाभ सीमित लोगों को मिलता है, जबकि पर्यावरण का नुकसान पूरी जनता को झेलना पड़ता है। यह एक प्रकार का पर्यावरणीय अन्याय है, जिसे राजनीतिक रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। राजनीतिक प्रदूषण को बनाए रखने में कभी-कभी मीडिया की भूमिका भी आलोचनीय रही है। कई मीडिया चैनल पर्यावरणीय मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देते या उन्हें राजनीति से जोड़कर सनसनीखेज बना देते हैं। इससे लोगों का ध्यान असली मुद्दे से भटक जाता है।

हालांकि कुछ स्वतंत्र मीडिया संस्थान और पर्यावरण कार्यकर्ता इस दिशा में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक सरकार और राजनैतिक दल गंभीरता से इन मुद्दों को नहीं लेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं है। राजनीतिक प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि समस्या के समाधान की वास्तविक इच्छाशक्ति खत्म हो जाती है। नीतियाँ बनती हैं, लेकिन लागू नहीं होतीं। बजट आवंटित होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। और इस सबका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है: खराब हवा से फेफड़ों की बीमारियाँ, गंदा पानी पीने से बच्चों में कुपोषण, वन क्षेत्र नष्ट होने से जलवायु परिवर्तन, गर्मियाँ अधिक गर्म और सर्दियाँ अधिक जहरीली होती जा रही हैं।

राजनीतिक प्रदूषण की समस्या को समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं! जब आम नागरिक पर्यावरण को लेकर सजग होंगे और सरकार से जवाबदेही मांगेंगे, तब ही राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा होगी। पर्यावरण से जुड़ी नीतियों को मजबूत, पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनाना जरूरी है। राजनीतिक एजेंडे में पर्यावरण को केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि नीति निर्धारण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका और स्वायत्त निकायों को पर्यावरणीय मामलों में तेजी से और निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।

निष्कर्ष--राजनीतिक प्रदूषण एक गंभीर लेकिन नजरअंदाज की गई समस्या है, जो न केवल पर्यावरणीय संकट को बढ़ा रही है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर कर रही है। जब तक राजनीति में पर्यावरण को केवल एक चुनावी मुद्दा समझा जाएगा और वास्तविक समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी। आज जरूरत है उस राजनीतिक प्रदूषण को खत्म करने की, जो असली प्रदूषण को खत्म नहीं होने देता।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जयपुर के वास्तुकार प्रमोद जैन को मुम्बई में डिज़ाइन स्केप पुरस्कार-2025 मिला

जयपुर। जयपुर के मशहूर वास्तुकार प्रमोद जैन, मेसर्स प्रमोद जैन एंड एसोसिएट्स ने प्रतिष्ठित डिज़ाइन स्केप पुरस्कार-2025 प्राप्त किया है। प्रमोद जैन और उनके सहयोगियों को यह पुरस्कार मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर (एमआईसी), जोधपुर की डिजाइन के लिए सरकारी और नागरिक भवनों की श्रेणी में दिया गया है।

- **प्रमोद जैन और उनके सहयोगियों को यह पुरस्कार मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर (एमआईसी), जोधपुर की डिजाइन के लिए सरकारी और नागरिक भवनों की श्रेणी में दिया गया है**

प्रमोद जैन ने यह पुरस्कार गुरुवार को सायं मुंबई के एक होटल में आयोजित एक भव्य समारोह में प्राप्त किया। उन्हें यह पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष मिला। पिछले वर्ष, उन्हें ऑडिटोरियम और एरीना की श्रेणी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के लिए डिज़ाइन एस्केप पुरस्कार मिला था। इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, रियल एस्टेट की शीर्ष हस्तियाँ और मुंबई के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। यह समारोह इकोनॉमिक टाइम्स राष्ट्रीय मीडिया समूह द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर (एमआईसी) की प्रशंसा एक समकालीन वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में की, जो कि जोधपुर की स्थापत्य विरासत से गहराई से जुड़ा है।

सूरसागर बलुआ पत्थर और पारंपरिक निर्माण तकनीकों से निर्मित, यह केंद्र आधुनिक तकनीक, नवाचार और कार्यक्षमता के साथ क्षेत्रीय चरित्र को कुशलतापूर्वक एकीकृत करता है।एमआईसी राजस्थान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें 1350 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें जोधपुरी पत्थरों से बना एक प्रतिष्ठित अग्रभाग है, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार, स्तरित छतें और पत्थर के स्तंभ, जालियाँ, कोष्ठक, दासा और छज्जा जैसी पारंपरिक सजावटें हैं। विशालता, भव्यता और सांस्कृतिक प्रतीकों का यह संगम एमआईसी को शहर का एक विशिष्ट स्थल बनाता है।

वास्तुकार प्रमोद जैन।

महाजन फायरिंग रेंज में बीएसएफ की आर्टिलरी रेजीमेंट ने लक्ष्य भेदकर ताकत दिखाई

बीकानेर, (निसं)। महाजन फायरिंग रेंज एक बार फिर धमाकों से गूंज उठी। बीएसएफ की आर्टिलरी रेजीमेंट ने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन कर गनों से सटीक निशाने साधे। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने लाइव फायरिंग देखी।

- **बीएसएफ की आर्टिलरी रेजीमेंट ने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन कर गनों से सटीक निशाने साधे**
- **बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने लाइव फायरिंग देखी और हथियारों का जायजा लेकर जवानों की हौसला अफजाई की**

महाजन फायरिंग रेंज में पिछले करीब एक महीने से बीएसएफ की 1044 आर्टिलरी रेजीमेंट को सालाना शूटिंग कोर्स चल रहा है। जवान इस दौरान आर्टिलरी गन से निशाने साधकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। महानिदेशक दलजीत सिंह इस सिलसिले में दिल्ली से विमान द्वारा यहां पहुंचे। महाजन रेंज पहुंचकर लाइव फायरिंग देखी और हथियारों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने गन पोजीशन पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की। साथ ही उनके समर्पण और प्रयास की सराहना की। डीजी ओपी प्वाइंट पर भी गए।

सेना से ड्रोन खतरों पर चर्चा

: डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी ने सेना की रणबांकुरा डिवीजन के मेजर जनरल दीपक श्योराण से सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन खतरों से निपटने पर चर्चा की। दोनों उच्च सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे सीमा के हालात पर मंथन किया। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग, डीआईजी अजय लूथरा, डीआईजी प्रधान स्टाफ वीएम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। रेंज के आईजी हेमंत शर्मा और एसपी कावेंद्र सागर ने भी डीजी से मुलाकात की तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के हालात पर बातचीत की।

लाइव फायरिंग के दौरान आर्टिलरी गन से सामरिक स्थिति के अनुसार विभिन्न टारगेट साधे गए। न्यू जेनरेशन इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट शक्ति पर ब्रीफिंग तथा उनका प्रदर्शन किया गया। डीजी चौधरी ने बताया कि स्थापना के बाद से बीएसएफ आर्टिलरी अपने आदर्श वाक्य ''लक्ष्य, निश्चय, विजय'' पर खरी उतरी है। रेंज में ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह चीमा (सेवानिवृत्त), डीआईजी/कमांडर (आर्टिलरी) ने डीजी का स्वागत किया।

राशिफल शनिवार 13 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, कृत्तिका नक्षत्र दिन 10:11 तक, हर्षण योग दिन 10:32 तक, वणिज करण प्रात: 7:24 तक, चन्द्रमा आज सायं 5:31 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवि योग दिन 10:11 तक है और पुन: दिन 3:41 से आरम्भ होगा। त्रिपुष्कर योग प्रात: 7:24 से दिन 10:11 तक है। आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग दिन 10:11 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रात: 7:24 से सायं 6:14 तक रहेगी। आज मंगल तुला राशि में रात्रि 9:23 से प्रवेश करेगा। आज सप्तमी तिथि का क्षय हुआ है। आज सप्तमी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:47 से 9:19 तक, चर 12:23 से 1:55 तक, लाभ-अमृत 1:55 से 4:59 तक।
राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:15, सूर्यास्त 6:31

मेष
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है, उचित परामर्श मिलेगा। आज व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आज यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कुंभ
घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।